Drug Price Equalisation Account and amounts so recovered shall be utilised for the purpose mentioned in DPCO 1979/1987 and, wherever necessary the Ministry of Law Justice and Company Affairs is consulted.

मध्य प्रदेश के बन्द पड़े उर्वरक एकक

316. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कतिपय उर्वरक एकक बन्द पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है, और ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन एककों को क्या-क्या सुविधायें/सहायता दी गई हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के मुताबिक मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम आकार के निम्नलिखित सिंगल सूपर फास्फेट (एस एसपी) संयंत्र मुद्रा की उपलब्धता और वितरण समस्याओं के कारण 31-5-94 से बन्द पड़े थे।

1. बी ई सी फर्टिलाइजर्स, भिलाई ।

2. खेतान मिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स निमरानी ।

3. यूनी अल्केम फर्टिलाइजर्स रायसेन ।

4. हर्षवर्धन केमिकल्स एण्ड मिनेरलस लि0, अंतरवे लिया ।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं, जिनसे एसएसपी एककों को भी लाभ होगा : —

I. फास्फेटिक उर्वरकों और उनके कच्चे मालों के लिए रेलवे भाड़े में कम की गई है,

II. नियंत्रण मुक्त फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने तथा आयातित उत्पादों के साथ स्वदेशी एककों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए स्वदेशी डीएपी पर 1000 रु० प्रति टन की रियायत तथा स्वदेशी कम्प्लेक्स उर्वरकों और एसएसपी पर समानुपातिक रियात दी जा रही है और;

III. सबद्ध एककों से अपेक्षित उत्पादन आंकड़े आदि प्राप्त करने के पश्चात् पुरानी राजसहायता देयों को प्राथमिकता के आधार पर चुकाया जा रहा है।

Mechanism for controlling Drug Prices

317. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are evolving a new transparent mechanism on the lines of BICP for controlling drug prices; and

(b) if so, what are the broad features of this new organisation to deal exclusively with the issue and the Ministry under whose administrative and technical control it will function?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (b) The Review of Drug Policy 1986 which includes the pricing aspects, is still to be finalized.

Package for the revival of sick fertilizer units

318. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be please to state:

(a) whether Government have finalised a new package for revamping the old and ailing fertilizer units in the public sector, in the light of the findings of the Expert Committee, appointed in June last, to come up with detailed proposals for making these units productive again;

(b) if so, what are its broad features; and

(c) to what extent this package envisages private sector participation in making these ailing units productive and contribute much needed fertilizer to the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has declared two fertilizer producing public sector undertakings, namely, Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) and Hindustan Fertilizer Corporation of India Ltd (HFC) as sick companies under the provisions of the sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. The BIFR has appointed Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. (ICICI) as the Operation Agency to prepare revival/rehabilitation packages in respect of these companies. Any decision on the revival of these companies, including the role of private sector in their revival, would depend upon the outcome of the proceedings pending before the BIFR, which is a quasi-judicial authority.

Government have not finalised any new package for revamping the sick fertiliser units in the public sector. A Technical Committee was set up in June, 1994 merely to assess the minimum requirement of funds for replacement of trouble prone equipment etc. in respect of a few units of HFC, and to assess the levels of production likely to be achieved after the above investments and to workout financial viability of these investments under alternative scenarios.

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं

319. **श्री अजीत जोगी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कतिपय पुनर्वास परियोजनाओं का परित्याग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी वैकल्पिक पुनर्वास योजनायें शुरू की गई हैं/शुरू करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फ्लैरियो) : (क) से (घ) भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना को मध्य प्रदेश सरकार कार्यान्वित कर रही है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस कार्य योजना के अधीन कुछ स्कीमें अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा, प्रोटीन की कमी दूर करने की स्कीम घरों और बस्तियों, सेवा केन्द्रों का पुनर्निर्माण, स्टेप-अप सब्सिडी तथा स्टाफ वृत्तिका या तो इसी तरह की स्कीमों से परस्परव्यापी (ओवर-लैपिंग) थी या यह पाया गया था कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अतः इन्हें समाप्त कर दिया गया था और इस तरह से बचे धन को अन्य स्कीमों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया था।

कोरबा उर्वरक संयंत्र

320. **श्री अजीत जोगी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उर्वरक संयंत्र की लाखों रुपयों की मशीनरी कोरबा में निष्क्रिय पड़ी है क्योंकि भारतीय उर्वरक निगम प्रस्तावित उर्वरक एकक को स्थापित करने में असफल रहा है ;

(ग) इस मशीनरी तथा अन्य निर्माण सामग्रियों को उपयोग में लाने की सरकार की क्या योजना है ;